Media coverage on information regarding the order from Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi in WP(C) 7526/2020

Amar Ujala
08.06.2021

निजी स्कूलों के वार्षिक-विकास शुल्क वसूलने पर रोक नहीं

हाईकोर्ट ने फिलहाल एक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को वार्षिक व विकास शुल्क वसूलने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में फिलहाल निजी स्कूलों की एक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार व कई अन्य छात्रों ने सिंगल के फैसले को दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। सरकार व छात्रों ने तर्क रखा है कि हाईकोर्ट के सिंगल जज का फैसला कानून के खिलाफ व अधूरे तथ्यों पर आधारित है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली व न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सिंगल जज के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस याचिका पर 10 जुलाई को नियमित खंडपीठ सुनवाई करेगी। अदालत ने करीब 450 निजी स्कूलों की एक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाए।

सुनवाई के दौरान हालांकि निजी स्कूलों ने याचिका पर आपत्ति जताई लेकिन साथ ही अदालत को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक वे छात्रों से फीस वसूलने के मामलों में मौजूदा सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे। फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने पर दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखना शुरू किया तो अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकलुभावन सरकार मत बनो, स्कूलों को भी पैसा दें। विकास सिंह ने कहा कि सिंगल ने जज स्कूल की फीस वसूली पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की व्याख्या का निष्कर्ष पर पहुंचने पर गंभीर रूप से गलती की। इस फैसले में इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राजस्थान राज्य से संबंधित है और ट्यूशन फीस लगाना उस समय के लिए था जब स्कूल वहां फिर से खुल गए थे।

उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा शपथपत्र का हवाला देते हु कहा कि स्कूलों ने स्वयं माना है कि ट्यूशन फीस की 60 प्रतिशत राशि वेतन के प्रति अपनी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त थी और शेष राशि अन्य खर्च मदों के लिए है। दिल्ली सरकार ने चुनौती याचिका में कहा कि पिछले साल अप्रैल और अगस्त के उसने आदेश व्यापक जनहित में जारी किए गए थे क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग वित्तीय संकट में थे। वहीं छात्रों ने अपनी अपील में कहा कि जब स्कूल ही बंद हैं तो भवनों की मरम्मत, प्रशासनिक खर्च, किराया और हॉस्टल खर्च लागू नहीं होते। उन्होंने तर्क दिया कि वार्षिक और विकास शुल्क को मात्र स्थगित किया गया था और लेने से रोका नहीं गया था। महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद स्कूल इस मद में शुल्क ले सकते हैं।

दिल्ली सरकार व छात्रों ने सिंगल जज के फैसले को दी है चुनौती

एकल जज का ऑर्डर : न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने अपने 31 मई के फैसले में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बच्चों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल 20 व 28 अगस्त 20 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों द्वारा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। अदालत ने कहा कि स्कूल बंद रहे या खुले स्कूलों को कुछ मदों में खर्च करना ही पड़ता है। अदालत ने कहा था कि डीओई के पास निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करने का तब तक कोई अधिकार नहीं जब तक यह साबित न हो जाए कि वह मुनाफाखोरी कर रहे हैं।

सीए परीक्षा : संशे

नई दिल्ली। द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए की इंटरमीडिएट (नई व पुरानी स्कीम), फाइनल (नई व पुरानी स्कीम), फाउंडेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट (आईआरएम) टेक्निकल एग्जामिनेशन व इंटरनेशनल टेक्सेशन असेसमेंट टेस्ट की परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया है।

शेड्यूल के मुताबिक सीए फाउंडेशन की परीक्षाएं 24 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई व 30 जुलाई को होंगी। फाउंडेशन के पेपर-1 और पेपर-2 के लिए परीक्षा अवधि तीन घंटे की है। यह परीक्षा दोपहर दो बजे से पांच बजे तक होगी। जबकि पेपर-3 व पेपर-4 की परीक्षा की परीक्षा अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक होगी। वहीं इंटरमीडिएट (ओल्ड स्कीम व न्यू स्कीम) की ग्रुप-1 की परीक्षा 6, 8, 10, व 12 जुलाई को आयोजित होगी। ग्रुप-2 की परीक्षा 14, 16, 18 जुलाई को

12 तदर्थ शिक्षव के लिए सीएम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने अब विवेकानंद महिला कॉलेज के 12 तदर्थ शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से न्याय की गुहार लगाई है। ड्टा के आह्वान पर शिक्षकों ने मंगलवार को तदर्थ शिक्षकों की ज्वाइनिंग और कॉलेज की कार्यवाहक प्रिंसिपल को हटाने को लेकर एक हल्ला बोल ऑनलाइन धरना दिया। शिक्षकों ने

डीय में बिना बाधा शुरू हुए ओपन बुक एग्जाम

Media coverage on information regarding the order from Hon'ble High Court of Delhi at New Delhi in WP(C) 7526/2020

HT
08.06.2021

Fee order stands, parents must pay 1st instalment: HC

Richa Banka
richa.banka@htlive.com

NEW DELHI: City private schools on Monday assured the Delhi high court that they will give 15% concession on development fee and annual charges for the current academic year, and that these can be paid in six monthly instalments, even as a bench of justices Rekha Palli and Amit Bansal rejected a Delhi government plea to stay an earlier order allowing schools to levy such charges.

In a statement before the court, the Action Committee Unaided Recognised Private Schools (ACURPS) — a body of 450 private unaided schools in Delhi — said they will, till the next hearing, follow principles laid down by justice Jayant Nath in his order on May 31. Justice Nath ruled that schools may collect these charges for the last academic year, on a monthly basis, but only after a 15% reduction in the payable amount, in lieu of unutilised facilities (such as water and electricity) during the lockdown.

The state challenged the ruling on Friday, arguing that "schools being charitable organisations are adopting an inhumane approach by charging parents more in the unprecedented time of the pandemic".

The bench on Monday said, "We are rejecting the stay application," adding that the parents should pay the first instalment.

It also remarked that the state government should not be "populist", and asked them to give subsidies to the schools since they have to pay taxes.

"Please don't just be a populist government saying that oh we have done this. It's not a short term lockdown; things were different last year... The Delhi government should give some money (subsidy) to the schools," justice Palli said.

Justice Nath, in his order, quashed two orders issued by the Delhi government, on April 18 and August 28 last year, which restricted private schools in the city to collect additional charges. He, however, said students should not be barred from attending classes over the non-payment of the fees.

THE DELHI GOVT STANDING COUNSEL TOLD THE COURT THE STATE WILL CHALLENGE THE ORDER

Advocate Kamal Gupta, representing the private schools, said, "Schools have been standing right besides the parents in these tough times and in continuation to that have extended the reduction of 15% as also instalments system for this year's tuition and development fee".

Advocate Santosh Tripathi, standing counsel of the Delhi government, said the government will challenge the order as "it is in the teeth of several judgments of the division bench of the high court and the Supreme Court".

Senior advocate Shyam Diwan, counsel for (ACURPS), told the court on Monday that they will follow the principles laid down by the single judge for this academic year also.

Senior advocate Vikas Singh, for the Delhi government, argued that the extra charges such as the development fees was suspended as upgrades, improvements and maintenance are not required when schools are shut for more than a year-and-a-half and since there is no wear and tear in the furniture and fixtures.

Opposing the stay application, Diwan told the court that the Delhi government did not have the powers to issue such a diktat. He said the schools have not indulged in commercialisation and profiteering which has been noted by the single judge.

Advocate Khagesh B Jha, appearing for four private parties challenging the judgment, also said parents have received bills of around ₹1 lakh per child.

The court noting the submissions declined to grant stay and issued notice to the private schools on the plea by the city government.

The Delhi government did not respond despite repeated requests for comment.

All pending int to be conducte

Kainat Sarfaraz
kainat.sarfaraz@hindustantimes.com

NEW DELHI: A week after the cancellation of the Class 12 board examinations, the Central Board of Secondary Education (CBSE) on Monday allowed schools to complete the pending practicals and internal assessment in online mode.

Several schools across India said they were unable to conduct practical exams or internal assessment as schools were shut during the second wave of the Covid-19 pandemic. On Monday, the national board asked these schools to conduct the pending tests in "only online" mode and submit the marks to the board by June 28.

For subjects that need practicals, the external examiner will decide on the date for an online viva voce in consultation with the internal examiner. The board has asked schools to share the date of exams with students "well in advance" and share the link of the "online meeting" on the exam day.

"Regarding subjects for which the external examiner has not been appointed, the concerned school teacher of the subject will conduct the internal assessment based on the instructions given in the curriculum in online mode and upload the marks awarded at the link provided by the board," CBSE controller of examinations Sanyam Bhardwaj said in a letter to schools on Monday.

A government official said there are n school for the online exams.

Covaxin for 18-45 b only for 2nd dose, I

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi government on Monday told the Delhi high court that it has directed all state-run vaccination centres, private hospitals and nursing homes that Covaxin shots will only be administered to those due for their second dose in the 18-45 age group, a day after it passed an order to this effect, even as residents of the Capital who booked slots for a first dose of Covaxin complained that their appointments were cancelled.

Advocate Anuj Aggarwal, additional standing counsel of the Delhi government, told justice Rekha Palli that an additional 40,000 vials of Covaxin were arranged for the city on June 6 so that beneficiaries can be inoculated within the stipulated four-to-six-week period.

The submissions came while the court was hearing individual petitions by three Delhi residents who said they were not able to get their second Covaxin dose in the city and had to travel to other cities, such as Meerut and Chandigarh, to get the jab within the mandated timeframe.

Aggarwal told the court that the Delhi chief secretary in the June 6 order said the Delhi Disaster Management Authority (DDMA) directed that all private hospitals and nursing homes administering Covaxin to ensure jabs are given only to those in line for the second dose.

The Delhi government's health department on June 3 issued similar directions to all